

दिव्यांगजनों के लिये आवागमन की सुगमता

प्रलिस के लिये:

[केंद्रीय लोक नरिमाण वभिाग, दिव्यांगजन अधकिार अधनियिम, 2016, सुगम्य भारत अभयान](#)

मेन्स के लिये:

दिव्यांगजनों के लिये समावेशता और समान अधकिारों को बढावा देने का महत्त्व, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में [केंद्रीय लोक नरिमाण वभिाग](#) ने सार्वजनकि भवनों में दिव्यांगजनों (PwD) के लिये आवागमन में सुधार करने हेतु कदम उठाए। [दिव्यांगजन अधकिार अधनियिम, 2016](#) के प्रावधानों के बावजूद दिव्यांगजनों से संबंधति चुनौतयिँ बनी हुई हैं जसके कारण CPWD ने भवनों में आवागमन की सुगमता मानकों का अनुपालन सुनश्चिति करने के लिये सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वन कयिा।

दिव्यांगजन अधकिार (RPwD) अधनियिम, 2016 क्या है?

परचिय:

- RPwD अधनियिम, 2016, [दिव्यांगजन अधकिार पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय](#) का अनुसमर्थन करता है जसका अनुमोदन भारत द्वारा वर्ष 2007 में कयिा गया था।
 - इस अधनियिम ने नःशिक्त व्यक्ती (समान अवसर, अधकिार संरक्षण और पूरण भागीदारी) अधनियिम, 1995 को प्रतसिथापति कयिा।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नःशिक्त अथवा दिव्यांगजन की संख्या लगभग 26.8 मलियिन थी जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% है।
- [राष्ट्रीय प्रतदिरश सरवेक्षण कार्यालय](#) के आँकड़ों के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों का प्रतशित भारत की कुल आबादी का 2.2% है।
 - NSSO के 76वें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में प्रत 1,00,000 लोगों में से 86 व्यक्ती दिव्यांग थे।

दिव्यांगता की वसितारति परभाषा:

- इस अधनियिम में दिव्यांगता को एक वकिसशील और गतशील अवधारणा के आधार पर परभाषति कयिा गया है।
- RPwD अधनियिम, 2016 में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढाकर 21 कर दयि गए जसमें केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगता के और अधकि प्रकार शामिल कयिे जाने का प्रावधान है।

अधकिार और हकदारी:

- अधनियिम के तहत उपयुक्त सरकारों को दिव्यांगजनों के लिये समान अधकिार सुनश्चिति करने का कार्य सौपा गया है।
- अधनियिम के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों (चालीस प्रतशित अथवा उससे अधकि दिव्यांगता वाला व्यक्ती) और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लिये उच्च शकिषा में आरक्षण (न्यूनतम 5%), सरकारी नौकरयिँ (न्यूनतम 4%) और भूमिका आवंटन (न्यूनतम 5%) जैसे अतरिकित लाभ प्रदान कयिे जाते हैं।
- 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिये नःशिलक शकिषा की गारंटी का प्रावधान कयिा गया है।
 - सरकार द्वारा वतित पोषति और मान्यता प्राप्त शैक्षणकि संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शकिषा प्रदान करना अनवियर्य है।
- इस अधनियिम में सार्वजनकि बुनयिादी ढाँचे और सुवधाओं को दिव्यांग व्यक्तयिँ के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी तथा समावेशन को बढाने पर जोर दयिा गया।

सार्वजनकि भवनों के संबंध में आदेश:

- दिव्यांगजन अधकिार नयिम, 2017 का नयिम 15 केंद्र सरकार को दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनश्चिति करने हेतु सार्वजनकि भवनों के लिये दिशा-नरिदेश और मानक स्थापति करने का आदेश देता है।
 - इन मानकों में दिव्यांग जनों के लिये मानक नरिमति वातावरण, परविहन और [सूचना एवं संचार प्रौद्योगकिी](#) शामिल है।

- सार्वजनिक भवनों सहित प्रत्येक प्रतष्ठान को वर्ष 2016 के सामंजस्यपूर्ण दशा-नरिदेशों के आधार पर इन मानकों का पालन करना होगा।
- नयिम 15 में हाल के संशोधनों के अनुसार प्रतष्ठानों को वर्ष 2021 के सामंजस्यपूर्ण दशा-नरिदेशों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिससे दवियांग जनों के लिये सुगमता सुनश्चिति हो सके।
 - व्यापक दशा-नरिदेशों में दवियांग जनों के लिये रैंप, ग्रैब रेल, लफिट और शौचालय जैसी वभिन्न सुगमता सुवधाओं वाली योजना, नविदि एवं वशिषिटताओं को शामिल कया गया है।
 - दवियांग जनों के लिये समान पहुँच सुनश्चिति करने हेतु सभी भवन योजनाओं को इन दशा-नरिदेशों के अनुरूप होना चाहयि।
- मौजूदा इमारतों को अभगिम मानकों को पूरा करने, दवियांग जनों के लिये बेहतरसमावेशता को बढ़ावा देने की दशा में पाँच वर्ष के भीतर रेड्रोफटिगि से गुज़रना अनविर्य है।

नोट:

- **RPWD** अधनियिम, 2016 में 21 अक्षमताओं में अंधापन, दृषट-बाधति, **कुषट रोग से मुक्त वयकृति**, श्रवण वकियर/दोष (बहरा और सुनने में कठनिई), चलन-संबंधी वकिलंगता, बौनापन, **बौद्धकि अक्षमता**, मानसकि बीमारी, ऑटजिम स्पेक्ट्रम वकियर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्यूलर डिसिट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थतियि, **स्पेसफिकि लर्नगि डिसिबलिटी (डसिलेक्सिया)**, मल्टीपल स्केलेरॉसिस, वाक् एवं भाषा वकिलंगता, थेलेसीमिया, हीमोफीलिया, **सकिल सेल रोग**, बहु-वकिलंगता, **तेज़ाब हमले से प्रभावति** और **पारकनिसंस रोग** शामिल हैं।

दवियांगों के सशक्तीकरण से संबंधति अन्य पहल कया हैं?

- [अदवर्तीय अक्षमता पहचान पोर्टल](#)
- [दीन दयाल दवियांग पुनरवास योजना](#)
- [दवियांग जनों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फटिगि हेतु सहायता](#)
- [दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप](#)
- [दविय कला मेला 2023](#)
- [सुगम्य भारत अभियान](#)

सार्वजनिक भवनों में पहुँच के संबंध में कया चतिाएँ हैं?

- PwD और कार्यकर्त्ताओं की रपिर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में स्थापति दशा-नरिदेशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021 के नए दशा-नरिदेशों को राज्य सरकारों से इसी तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
 - वशिषेकों का कहना है कि कसि भी राज्य ने अभी तक अपने भवन उपनयिमों में सामंजस्यपूर्ण दशा-नरिदेशों को शामिल नहीं कया है, जो पहुँच के मुद्दों को संबोधति करने में व्यापक वफिलता का संकेत देता है।
- वशिषज्ज पहुँच संबंधी दशा-नरिदेशों को लागू करने के लिये ज़मिमेदार सार्वजनिक नरिमाण वभिगों के इंजीनयिरों के बीच जागरूकता और जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डालते हैं।
- रेड्रोफटिगि परयोजनाओं के लिये फंड उपलब्ध हैं, लेकिन कई राज्यों और शहरों ने उनके लिये आवेदन जमा नहीं कयि हैं, जो पहुँच पहल को प्राथमकिता देने में वफिलता का संकेत देता है।
- केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग के ज़ापन में स्पष्टता का अभाव है और इससे अनावश्यक संसाधन की बरबादी हो सकती है, जिससे पहुँच उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD)

- CPWD की स्थापना मूल रूप से जुलाई 1854 में अजमेर प्रोवजिनल डिवीज़न के रूप में की गई थी। इसका प्राथमकि उद्देश्य वास्तुकला, इंजीनयिरगि, परयोजना प्रबंधन और भवन नरिमाण तथा रखरखाव जैसे वषियों को शामिल करते हुए सार्वजनिक कार्यों को नषिपादति करना था।
- वर्तमान में, CPWD शहरी वकियस मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी राष्ट्रव्यापी उपस्थति है।
- CPWD केंद्र सरकार के प्रमुख इंजीनयिरगि ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीन प्रभाग, भवन और सड़क (Buildings and Roads- B&R), इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल (Electrical and Mechanical- E&M) एवं बागवानी शामिल हैं।
- वर्ष 2016 में CPWD ने 100 करोड़ रुपए के बजट से अधिक की सभी परयोजनाओं के लिये आधुनिक धूल-मुक्त नरिमाण वधियि, वशिष रूप से मोनोलथिकि प्रणाली को अपनाया।
 - मोनोलथिकि प्रणाली में बीम और स्लेब के लिये कंक्रीट का उपयोग करना शामिल है, जिससे एक एकीकृत नरिमाण घटक बनता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग वयक्तियों का घर है। कानून के अंतरगत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????????:

प्रश्न. क्या नःशिक्षित वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियावधिको सुनश्चिति करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/enhancing-accessibility-for-persons-with-disabilities>

